C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2021/1943 (Saka)

No. 24, Thursday, March 25, 2021/Chaitra 04, 1943 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 421 to 427	9-36
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 428 to 440	47-111
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060	112-756

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 758-763

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 764

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE 765-766

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 278th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Road Transport & Highways

Shri Nitin Jairam Gadkari 767

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on 'General Defence Budget, BRO, ICG, MES, DGDE, DPSUs, Welfare of Ex-Servicemen, Defence Pension and ECHS (Demand No. 19 & 22)' pertaining to the Ministry of Defence

Shri Shripad Yesso Naik 768

(iii)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Energy on 'Energy Conservation' pertaining to the Ministry of Power 769

(b)	Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Energy on 'National Electricity Policy-A review' pertaining to the Ministry of Power	769
(c)	Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Energy on 'Evaluation of Role, Performance and functioning of Power Exchange' pertaining to the Ministry of Power	770
(d)	Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Energy on 'Functioning of Central Electricity Regulatory Commission' pertaining to the Ministry of Power	
	Shri R.K. Singh	770
(iv)(a)	Status of implementation of the recommendations contained in the 138th Report of the Standing Committee on Commerce on 'Activities and Functioning of Spices Board' pertaining to the Ministry of Commerce and Industry	771
(b)	Status of implementation of the recommendations contained in the 150th Report of the Standing Committee on Commerce on "Export of Organic Products: Challenges and Opportunities" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry	
	Shri Hardeep Singh Puri	771

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON PERSONAL DATA PROTECTION BILL – EXTENSION OF TIME 772

MATTERS UNDER RULE 377 773-787

(i) Need to set up a Horticulture University in Dhar district, Madhya Pradesh

Shri Chhatar Singh Darbar 773

(ii) Need to extend intercity train (Train No. 02529) upto Bhatni Junction Railway Station in Deoria district, Uttar Pradesh

Shri Ramapati Ram Tripathi 774

(iii) Regarding boosting of tourism and employment opportunities in Jalgaon

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 775

(iv) Need to resume operation of Weaving Mill in Sandila Tehsil in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 776

(v) Regarding providing facilities to retired personnel of paramilitary forces at par with ex-servicemen

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 777

(vi) Regarding conversion of Uttarkashi-Kamad-Anyarkhal – Burhakedar - Ghansali - Mayali -Tilwara road in Uttarakhand as all weather National Highway

Shrimati Mala Rajya Laxmi Shah 778

(vii) Need to accord approval to the drinking water & irrigation project for Churu Parliamentary Constituency and Shekhawati Region in Rajasthan

Shri Rahul Kaswan 779

(viii) Regarding development of Jhansi and Lalitpur districts in Uttar Pradesh

Shri Anurag Sharma 780-782

(ix) Regarding running of Vande Bharat Train between Delhi and Gorakhpur and Shatabdi Express on Lucknow-Gorakhpur-Varanasi Railway section

Shri Ravindra Kushawaha 782

(x) Regarding Open Shelter Home for Orphan children run by Laveena Vikas Seva Sansthan, Ogana in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Arjun Lal Meena 783

(xi) Regarding railway related issues in Haryana

Shri Dharambir Singh 784

(xii) Regarding early construction of Chiraiya-Diphi-Ghorasahan road in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar

Shrimati Rama Devi 785

(xiii) Regarding alleged flouting of environmental norms at stone quarrying sites in Aurangabad district, Bihar

Shri Sushil Kumar Singh 786

(xiv) Regarding proper resolution to railway related issues of Shirdi Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Sadashiv Kisan Lokhande 787

VALEDICTORY REFERENCE 788-790

NATIONAL SONG 791

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 784

Member-wise Index to Unstarred Questions 785-790

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 791

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 792

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, March 25, 2021/ Chaitra 04,1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[SHRI BHARTRUHARI MAHTAB *in the Chair*]

HON. CHAIRPERSON: Now, Question Hour.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. CHAIRPERSON: Question No. 421 – Dr. Jayant Kumar Roy – Not present.

Shri Bhola Singh.

(Q. 421)

श्री भोला सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वह 'हरित' प्रस्ताव वायु प्रदूषण रोकने के लिए लिए लाए गए हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली में 49,930,15 पुरानी बसें हैं, जो दस से बीस साल पुरानी हैं और उत्तर प्रदेश में 56,54,759 बसें हैं। मैं बुलंदशहर से आता हूं जो कि दिल्ली का एनसीआर का हिस्सा है।

वर्ष 2020 में वायु प्रदूषण का इंडेक्स आया, जिसमें विश्व में 30 शहरों का प्रदूषण क्रम दिया गया है, जिसमें 22 शहर भारत के हैं, उसमें दिल्ली के बाद गाजियाबाद, बुलंदशहर प्रदूषण के मामले में तीसरे नम्बर पर आता है। जिस तरीक से माननीय मंत्री जी पुरानी बसों को हटाने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। मेरा ग्रामीण इलाका है, वहां करीब ढ़ाई सौ बसें ऐसी हैं, जो दस साल से कम की हैं और करीब सवा पांच सौ बसें इससे ज्यादा समय की हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एनजीटी ने अक्तूबर, 2017 को एक आदेश दिया था, जिसमें पुरानी बसों को 31 मार्च, 2021 तक की ही अनुमति दी थी। अगर ये सारी बसें हट जाती हैं तो वहां के नागरिकों को असुविधा होगी। इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या विचार करेंगे, जिससे लोगों को असुविधा न हो और वायु प्रदूषण भी कंट्रोल किया जाए, इसके लिए क्या आप कोई योजना बनाने के बारे में सोच रहे हैं?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्माननीय सभापति महोदय, एयर पोल्यूशन और वॉटर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारी स्वास्थ्य विषयक अनेक समस्याओं का संबंध पोल्यूशन से जुड़ा है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस समस्या की गंभीरता को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एक तरफ पोल्यूशन जिन कारणों से होता है, उसे कैसे कम करें। हम अपनी तरफ से लगातार पॉजिटिव प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल की बजाए इथेनॉल, मीथेनॉल, बायो-डीजल, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम कर रहे हैं।

मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 81 परसेंट लिथियम ऑयन बैटरी देश में ही बन रही है। दो सालों के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक फोर व्हिलर और डीजल बसों की कीमत इलेक्ट्रिक के ही समान यानी दोनों की कीमत एक समान होगी, इतना रेट कम हो जाएगा। हमारा पेट्रोल का कन्जम्पशन बीस हजार रुपये लगता है, वही इलेक्ट्रिसिटी का दो हजार रुपये लगेगा।

हमने प्रधानमंत्री जी के सांइटिफिक एडवाइजर, इसरो और डीआरडीओ को बुलाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी, उसमें लिथियम ऑयन के साथ एल्यूमिनियम ऑयन, जिंक ऑयन, सोडियम ऑयन और स्टील ऑयन पर भी काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जल्दी ही ब्रेकथ्रू मिल जाएगा और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ-साथ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी चेन्नई आईआईटी ने काफी अच्छा काम किया है, उन्होंने समुद्र के पानी से हाइड्रोजन निकालने के बारे में सक्सेसफुली प्रयोग किया है। उसके साथ-साथ सोलर एनर्जी से भी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

मिनिस्ट्री उन्हें सहयोग कर रही है, उनसे बातचीत और एमओयू कर रही है, ताकि देश में जल्दी ही ऑल्टरनेटिव फ्यूएल आए। कॉन्सटीट्यूशन के अनुसार ग्रीन टैक्स तय करने का अधिकार भारत सरकार का है। हम केवल प्रिंसिपली टैक्स तय करके राज्य सरकार को देते हैं। प्राइवेट व्हिकल्स 15 साल के बाद ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो उन पर यह टैक्स 10 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को देने के लिए अभी एडवाइजरी इश्यू की गई है।

इसके साथ ही जो कॉमर्शियल व्हिकल्स हैं, उन पर 8 साल के बाद टैक्स लगा सकते हैं। यह अधिकार राज्य सरकार को है कि कितना टैक्स लगाना है। माननीय सदस्य ने जो बात अभी की है, उसमें एक सॉल्यूशन है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्जे में डूबा हुआ है, वहां पर परिस्थितियां खराब हैं। गरीब लोगों को बहुत अड़चन होगी। इसलिए निश्चित रूप से उनके प्रति सहानुभूति से सोचना होगा। एक तरफ पॉल्यूशन रोकने के लिए स्ट्रिक्ट नियमों का पालन भी करना होगा। दूसरी ओर गरीब आदमी की समस्याओं को भी संवेदनशीलता के साथ देखना होगा। मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि अगर वे डीजल की बसों को सीएनजी में कंवर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन कम होगा। सरकार इसके बारे में सहानुभूति से सोचेगी और वे बसें फिर से कुछ दिनों तक चल सकेंगी।

माननीय सभापति जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे हुए भागों में राइस स्ट्रॉ निकलता है, जिसे पॉपुलरली पराली कहा जाता है। अब सक्सेज़फुली यह प्रयोग भी हुआ है कि पूरे देश में जहां भी राइस की उपज है, वहां पर five tonnes of rice straw is giving one tonne of bio-CNG. मैंने अपने मतदान क्षेत्र नागपुर में 450 पुरानी बसों को सीएनजी में कंवर्ट करने का निर्णय किया है, जिनमें से 100 बसें कंवर्ट भी हो गई हैं। इससे इकोनॉमिक्स भी बदल गई है। बायो-सीएनजी से चलने वाला एक ट्रैक्टर भी लांच किया है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य इस दिशा में भी कोशिश करें।

इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज है। दिल्ली के आस-पास जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसे रोकने के लिए हमारी मिनिस्ट्री की ओर से करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च करके रोड बनाए जा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाइवे 10,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। ईस्टर्न और वेस्टर्न बाइपास करीब 20,000-22,000 करोड़ रुपये के हैं। इसके साथ ही साथ और भी रोड्स हैं, जिनके पूरा होने से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आने वाले दो-तीन सालों में दिल्ली-मेरठ पूरा हो जाएगा। हम दिल्ली से देहरादून के लिए रोड बना रहे हैं, जिससे देहरादून सिर्फ दो घंटे में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से लखनऊ के लिए रोड बन रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़, देहरादून और हरिद्वार केवल दो घंटे में जा सकेंगे। दिल्ली से जयपुर सवा दो घंटे में जा सकेंगे। दिल्ली के आस-पास जब ये सारे नेटवर्क तैयार

होंगे, दिल्ली से कटरा, अमृतसर वाला नया रोड भी बन रहा है, उसका भी काम शुरू होगा, इसके कारण काफी समस्याएं कम हो जाएंगी। दिल्ली का प्रॉब्लम क्रूशियल प्रॉब्लम है। हमें एयर और वॉटर पॉल्यूशन दोनों के लिए गंभीरता से सोचना होगा, उसी के लिए ये नियम बनाये जा रहे हैं।

श्री भोला सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने पॉल्यूशन की समस्या को कंट्रोल करने के साथ-साथ नागरिकों की समस्या का समाधान भी निकाला है। मैं भी एनसीआर से हूं और मैं कहना चाहूंगा कि हाइवे और ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल का लाभ पूरे एनसीआर के लोगों को मिला है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं ग्रीन टैक्स के संबंध में एक और जानकारी लेना चाहता हूं कि ग्रीन टैक्स का कलेक्शन जिस क्षेत्र से होगा, जैसे एनसीआर का यहां से होगा और बुलंदशहर का बुलंदशहर से होगा। क्या उस क्षेत्र के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उस टैक्स को उसी क्षेत्र में बसों या अन्य किसी क्षेत्र के माध्यम से लगाने की योजना है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सभापति महोदय, हमें कॉन्सटीट्यूशन केवल प्रिंसिपली टैक्स लगाने का अधिकार देता है। हम फिर राज्य सरकार को 10 से 25 प्रतिशत टैक्स कलैक्ट करने का अधिकार देते हैं। टैक्स 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत या 15 प्रतिशत लिया जाएगा, यह राज्य सरकार का अधिकार है। हम अपेक्षा करते हैं कि ये पैसे लेने के बाद वे बजट बढ़ाकर पॉल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए काम करें।

इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि पॉल्यूशन करने वाले व्हिकल को लोग तुरंत बदल भी दें। मैंने पिछली बार सदन में बताया था कि जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने एक स्कूटर खरीदा था। वह स्कूटर 24 किलोमीटर प्रति लीटर चलता था।

मैंने 24 किलोमीटर प्रति लीटर वाली स्कूटर खरीदी थी। उन्होंने बोला था कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। आज 85 किलोमीटर प्रति लीटर वाले व्हीकल्स आ गए हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी के साथ जाने में आर्थिक बचत

भी है। पुरानी गाड़ियां धुआं छोड़ती रहती हैं और एवरेज कम देती हैं। इनकी मेनटेनेन्स कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। यह कन्ज्यूमर के भी हित में है, इसीलिए धीरे-धीरे लोग इस प्रकार के व्हीकल्स को निकालकर इनकी स्क्रैपिंग करें। स्क्रैपिंग के बाद उनको नए व्हीकल खरीदने पर 5 परसेंट का कंसेशन भी मिलेगा। हमने यह भी किया है। काफी कुछ अन्य कन्सेशन्स भी दिए हैं। देश में डीजल और पुराने व्हीकल्स के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा था, उसे धीरे-धीरे कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अल्टीमेटली यह पैसा राज्य सरकार का है। इस पैसे को कहां खर्च करना है, कहां नहीं खर्च करना है, यह उनका अधिकार है। हम केवल 10 से 25 परसेंट तक यह टैक्स ले सकते हैं। 15 साल पुराने जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं और 8 से ज्यादा पुराने जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके लिए यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।

माननीय सभापति: पूरे विश्व में अकेला भारत ही ऐसा देश है, जहां भारत पूछता है कि 'कितना पीता है'। यह काँशियसनेस हमारे देश में काफी ज्यादा है। श्री मनीष तिवारी जी।

श्री मनीष तिवारी: धन्यवाद सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में डीजल-पेट्रोल पर जो टैक्स है, उससे 4.3 लाख करोड़ रुपया केन्द्र सरकार कमाएगी । उसके अलावा 13 से 16 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो एडीशनल सैस और सरचार्ज लगाया गया है, उससे केंद्र सरकार 1.87 लाख करोड़ रुपये कमाएगी। इसके अलावा 39 हजार करोड़ रुपये एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर सैस से कमाया जाएगा, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत का 37 प्रतिशत है। इसके अलावा राज्य सरकारें अपना अतिरिक्त टैक्स लगाती हैं। इसके ऊपर हम 'हरित टैक्स' को लगाने का प्रावधान कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं और साथ ही विनम्रतापूर्वक यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि अगर हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो सोच बदलने की जरूरत है। हमको ज्यादा पैसा एमआरटीएस के ऊपर खर्च करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहां पर सड़क बनती है, वहां पर फुटपाथ नहीं बनता है। क्या आपका मंत्रालय प्रदेश सरकारों को यह एडवाइजरी जारी करेगा कि जहां पर नैशनल हाईवे बनता है या जहां पर वे सड़क बनाएं, उसके साथ फुटपाथ जरूर बनाएं। बाइ-साइकिल ट्रैक जरूर बनाएं, क्योंकि आप जब तक लोगों की मानसिकता

नहीं बदलेंगे, तब तक गाड़ियां बढ़ती रहेंगी, प्रदूषण बढ़ता रहेगा और लोग टैक्स भी देते रहेंगे। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन के साथ एक छोटा सा सवाल है।

माननीय सभापति : जितना लंबा प्रश्न होगा, उतना लंबा जवाब होगा।

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उसमें कुछ सच्चाई है। हिंदुस्तान में विशेष रूप से पॉपुलेशन और व्हीकल पॉपुलेशन, इन दोनों की ग्रोथ बहुत फास्ट है। यह एक गंभीर समस्या है। घर में तीन लोग हैं, लेकिन उनके पास पांच गाड़ियां होंगी। पार्किंग के लिए जगह नहीं है, इसलिए वे रोड पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्करेज करना चाहिए। यह बात उन्होंने कही है और यह बिल्कुल सही है कि public transport will be cost effective, pollution free, indigenous, and bring about import substitution. अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे विभाग को ropeway, cable car, funicular railway and light rail transport ट्रांसपोर्ट का काम दिया है, यानी केवल मीटर गेज और ब्रॉडगेज को छोड़कर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का सारा काम भी दिया है। मैं घोषणा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कल ही मेरी एक डिटेल्ड मीटिंग हुई है और हम उसमें काफी आगे गए हैं। उस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें दिल्ली से मुंबई के 1300 किलोमीटर हाईवे को हम ई-हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर ट्रक और बसेज 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इलेक्ट्रिक से चलेंगी, जिस तरह से इलेक्ट्रिक रेलवे चलती हैं। सीमेन्स कंपनी ने इसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जर्मनी में रोड बनाई है। उन्होंने मुझे पूरा प्रेजेंटेशन दिया और बातचीत हुई। इस ई-हाईवे पर इस प्रकार के ट्रक और बसेज करने से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 70 परसेंट कम हो जाएगी, जिससे यह काफी सस्ता हो जाएगा। इसमें ट्रॉली बस भी जा सकती है। आपका कहना बिल्कुल सही है राज्य सरकार और भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा प्रायॉरिटी दें।

दूसरी इम्पोर्टेंट चीज आपने कही, वह भी सही है कि पहली प्रायोरिटी वॉटर वेज़, दूसरी रेलवे, तीसरी प्रायोरिटी रोड्स और चौथी एविएशन होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, कभी-कभी मुझे भी लगता है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है कि अब देश का 85 परसेंट ट्रैफिक रोड पर बढ़ रहा है और दिन

प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है। इससे एनएचएआई और हमें फायदा होता है, लेकिन यह चिंता का विषय भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एंक्रेज करने की आपकी बात बिलकुल सही है। सरकार इसके लिए नीति बना रही है और मेट्रो अनेक गांवों-शहरों तक पहुंचा रही है। मेट्रो की प्रति किलोमीटर कॉस्ट 350 करोड़ रुपये है। परसों पीयूष जी के साथ हमारी मीटिंग नागपुर में पहली बार हुई थी। हम लोग 850 किलोमीटर एग्जिस्टिंग ब्रॉड गैज मेट्रो ट्रैक का उपयोग करके, 140 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली और हर स्टेशन पर रूकने वाली मैट्रो का कर रहे हैं। ऐसे अनेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपाय कर रहे हैं। आपने जो बात पेट्रोल-डीज़ल के टैक्सेशन के बारे में कही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल-डीज़ल पर जो टैक्स लगते हैं, राज्य और भारत सरकार लगाती है। लेकिन टैक्स को कितना कम करना है या ज्यादा करना है, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस बारे में निर्णय करता है। आपने जो भावना बतायी है, वह उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

आपने फुटपाथ के बारे में जो कहा है, वह बिलकुल सही है। एनएचएआई के पुराने रोड- आप सब लोग इसके लिए मुझे प्रपोज़ल दीजिए कि हमारे जो पुराने रोड जो शहर के बीच में से जाते थे और हम बायपास बनाते थे, उसको हम छोड़ देते थे। हम उस पर काम नहीं करते थे। हम कहते थे कि हमने अब नया रोड बना लिया है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। वह रोड, जो शहर के अंदर है और उस पर एनएच का नाम है, उसको हम सीमेंट-कंक्रीट के व्हाइट टॉपिंग से चैंज कर देंगे। वहां फुटपाथ बनाएंगे, साइकिल ट्रैक बनाएंगे, सीनियर सिटिजन के बैठने के लिए जगह भी बनाएंगे। ऐसे करीब 60-70 प्रपोजल मैंने मंजूर किए हैं। आपकी कॉन्स्टीटयुएंसी में जितने पुराने गांवों और शहरों से जाने वाले एनएच अधूरे पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर न नगर परिषद काम करती है, न कॉर्पोरेशन काम करती है, न स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसका प्रपोज़ल मुझे लाकर दीजिए। मैं उसको अच्छे तरीके से कर दूंगा और वहां साइकिल ट्रैक बना दूंगा।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे ई-रिक्शा के लिए हमने किया है। पहले लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। इसी सदन में आप सब लोगों के सहयोग से हमने बिल पास किया। काफी अड़चनें आयीं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। लेकिन अब देश में एक करोड़ में से शायद,

कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तो आदमी रिक्शा खींचता था, अब वह प्रथा बंद हो गयी है और हमने ई-रिक्शा की शुरूआत की है। हमारी सरकार की गरीबों के लिए, विशेष रूप से जिनका शोषण होता था, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे मनीष जी, अभी एक अच्छी बात आयी है और वह है ई-साइकिल। स्कूटर-मोटरसाइकिल पर डिलीवरी करने पर 6-6.5 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आता है। मेरे मन में आइडिया है कि ई-साइकिल का खर्च दो रुपये प्रति किलोमीटर आएगा तो क्यों नही ई-साइकिल को हम पॉप्युलर करें और सामानों की डिलीवरी देने के लिए ई-कार्ट और ई-साइकिल को बढ़ावा देंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। हमारे राज्य मंत्री मनसुख भाई पार्लियामेंट रोज साइकिल चलाकर आते थे। उनका बहुत अच्छा उदाहरण है। हमें साइकिल को और पॉप्युलर करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है। आप सब लोग अपने यहां साइकिल को एंकरेज कीजिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे सेक्रेटरी युद्धवीर मलिक थे, उनका बेटा आईएएस ऑफिसर है, जो बिजनौर में कलेक्टर है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में पड़ी पुरानी साइकिल खरीद ली, उसको पीला रंग दिया और ऐसी दो-ढाई सौ साइकिल गरीब लोग यूज़ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में साइकिल और स्कूटर सढ़ रही थीं क्योंकि न्यायालयों में केसेस होते हैं। उसका ऑक्शन निकालकर, रिपेयर करके एनजीओ को देकर और हम अलग-अलग जगह रख देंगे तो लोगों को फायदा होगा और पेट्रोल डीज़ल से भी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए कोई अलग से मेकेनिज्म करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव आप सब लोग भी जरूर कीजिए। हमारे विभाग की ओर से जहां भी सहयोग होगा, हम लोग जरूर करेंगे।

HON. CHAIRPERSON: Question No. 422. Shri C.P. Joshi.

(Q. 422)

श्री सी.पी. जोशी: सभापति महोदय, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा कि पिछले 6-7 वर्षों में देश भर में सड़कों के क्षेत्र में हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो या इस दिशा में नये नवाचार हों, विशेष रूप से मंत्री महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने फोर लेन, सिक्स लेन और कई नवाचार इस देश में दिए हैं। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय आपका बहुत-बहुत आभार।

देश में फोर लेन और सिक्स लेन के किनारे पर बहुत बड़े क्षेत्र में जमीन हाईवे के पास है और वह आपके मंत्रालय के पास है। देश में बढ़ती हुई ऊर्जा को देखते हुए क्या सोलर एनर्जी के बारे में, इस दिशा में कोई विभाग विचार कर रहा है। क्योंकि रेलवे ने भी इस दिशा में नवाचार किया है। आज वहां अगर सोलर एनर्जी आती है, रात्रि को लाइट लगाने के लिए या और कोई कमर्शियल यूज के लिए, तो क्या सड़क परिवहन मंत्रालय इस दिशा में कोई विचार कर रहा है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत अच्छी सूचना है। ऑलरेडी हम टोल प्लाज़ा एरिया, रेस्ट एरिया, ट्रक ले बाय, बस-बे, बस शेल्टर्स, ग्रेट सैप्रेटर स्ट्रक्चर्स, इंटरचेंजिस फ्लाईओवर्स, अण्डरपासेज़, व्हीकुलर पेडस्ट्रियन एण्ड ओवरपासेज़, बिल्टअप सेक्शंस, आदि अनेक जगहों पर इस सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अनुभव भी आए हैं। हमने अभी दिल्ली-मेरठ हाईवे पर, जो पहला 16 लेन रोड दिल्ली में बनाया था, वहां हमने सोलर पैनल्स पर लाइट्स लगाए थे तो हमारे सोलर पैनल्स ही लोग चोरी कर के ले गए। उसके कारण दिक्कत आई। यह दिल्ली के एरिया में हुआ था। पर हम लोग अभी ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर लगाएंगे जहां कोई पहुंच नहीं पाएगा।

दूसरा, इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे के दुहाई इंटरचेंज पर 382 केडब्ल्यूपी और डासना इंटरचेंज पर 450 केडब्ल्यूपी कैपेसिटी का लगाया है और इसके साथ हम लाइट भी इसके ऊपर लगा रहे हैं। Minimum street lights require for illumination is 40 lakhs. वह भी इसमें से मिल रही है। हम लाइटिंग लगभग सोलर पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसकी

जितनी जगह खाली हो सकती है, पहले पेरिफेरल रोड बाइंडिंग में फिर लगे तो रोड बड़ी करनी पड़ती है तो दिक्कत आती है। निश्चित रूप से जहां-जहां हो सकेगा, वहां सोलर की व्यवस्था तैयार कर के, निश्चित रूप से उसको एनकरेज करने की कोशिश करेंगे।

श्री सी.पी. जोशी: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। इस दिशा में राजस्थान में फोर लेन से सिक्स लेन भी बने हैं। ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर भी है। गोल्डन कोरिडोर भी है। क्या राजस्थान में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कुछ रोड्स को लेने का मंत्रालय ने कोई विचार किया है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जहां-जहां मौका है, जहां-जहां लाइट लग रही हैं, वहां-वहां हम रूफ टॉप पर कर रहे हैं। वैसे यह इस विषय से संबंधित नहीं है, पर अभी वर्ल्ड बैंक ने हमारे एमएसएमई विभाग को चार हजार करोड़ रुपये दिए हैं, स्टेट बैंक उसकी ऐजेंसी है। जितनी हमारी एमएसएमई की इंडस्ट्रीज़ हैं, वे रूफ टॉप सोलर लगाएंगी। उसके लिए वर्ल्ड बैंक का बहुत कम ब्याज पर लोन उपलब्ध है। निश्चित रूप से सोलर की ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। प्रधान मंत्री जी का भी इसमें बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट है। हम इसमें अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में वर्ल्ड के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। हम लोग लगातार, जहां-जहां जगह मिलती है, वहां प्रयास करते हैं। केवल एक ही छोटा रिज़र्वेशन मेरे मन में है, जो सम्माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम रोड की विड्थ, जैसे अभी दिल्ली मुंबई में हमने 120 मीटर विड्थ जो है, जनरली रोड 48 मीटर में होती है। जो खाली जगह होती है, कभी भविष्य में जब हम लोग रोड को एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए जगह की जरूरत होती है। वहां पेड़ लगाते हैं तो हमको फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि पेड़ अगर उठाना है तो हमारी परमिशन लो। तो ये पेड़ लगाने से लोग बोलते हैं। नहीं लगाने से नहीं दिक्कत पैदा होती है। तो कभी न कभी ऐसी अड़चनें भी आती हैं। अगर सोलर लगा देंगे और रोड बड़ा करने के लिए फिर निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे सर्विस प्लेसेज़ हैं, हमारी एमिनिटीज़ हैं, हमारा टोल नाका है, रूफ टॉप जितना आता है, उसमें हम कर रहे हैं। रोड के बीच में भी

कहीं सोलर पर ही लाइट लगती है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी, सिंह साहब ने इसमें काफी अच्छा काम किया है। उनसे और भी कुछ नए आइडियाज़ ले कर, रोड में इसमें क्या हो सकता है, वह जरूर हम करने की कोशिश करेंगे।

HON. CHAIRPERSON: Question No. 423**.** Shri Bidyut Baran Mahato.

(Q. 423)

माननीय सभापति: महतो जी, सप्लिमेंट्री पूछिए।

श्री विद्युत बरन महतो: सभापति महोदय, शायद सदन में कोई ऐसा सदस्य होगा जो माननीय मंत्री जी की कार्यकुशलता का कायल नहीं है। मैं अपने क्षेत्र का एनएच-33, जो ओडिशा से संबंधित था, वह यूपीए सरकार के समय से लगभग छह साल से, कभी हाईकोर्ट, कभी सीबीआई, अैर कभी कॉन्ट्रेक्टर, इसी तरह से यह सन् 2010 से झूल रहा था।

माननीय और यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ। माननीय मंत्री जी ने एनएच-33 बनवाया। जमशेदपुर, जो ऐसी उद्योग नगरी है, जहां लगभग 10-12 उद्योग हैं, टाटा स्टील भी है, यहां लगभग 20,000 गाड़ियों का आना-जाना होता है। हम पिछले सप्ताह माननीय मंत्री से मिले थे और अनुरोध किया कि जमशेदपुर में एलिवेटिड कॉरिडोर नहीं बना तो यह जामनगर बन जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी को कार्यकुशलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने तुरंत फोर लेन नहीं बल्कि सिक्स लेन एलिवेटिड रोड की स्वीकृति दी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को जमशेदपुरवासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं।

माननीय मंत्री जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में लगभग 18 सेवाओं में ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण आधारित संपर्क रहित सेवा के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस अत्यंत जनहित एवं क्रांतिकारी शुरूआत के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अशिक्षित एवं निर्धन व्यक्ति, जिन्हें कम्प्यूटर शिक्षा में प्रवीणता हासिल नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की सहायता में आरटीओ में किस प्रकार व्यवस्था की जाएगी? नागरिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं, क्योंकि साइबर अटैक और हैकिंग जैसे साइबर क्राइम से ई-परिवहन और ई-वाहन की वैबसाइट को बचाना नितांत आवश्यक है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी ने जब से प्रधान मंत्री पद की शपथ ली है, तब से मोदी जी लगातार ईज़ ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमने करीब 1400 से 1500 पुराने कानून खत्म कर दिए। सभी डिपार्टमेंट्स को उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ बिजनेस के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। इतना ही नहीं, ईज़ ऑफ बिजनेस पर हमने डिपार्टमेंट में क्या-क्या किया है, इसके बारे में उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट मांगी और हमें एक्टिवेट और मोटिवेट किया।

महोदय,विशेषकर आप सबका काम आरटीओ में होता है, यह मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आरटीओ में सबसे बड़ा रिफॉर्म किया है – the historic move to make services of the Transport Department citizen-centric and hassle-free to boost ease-of-doing-business; 18 contactless RTO services can now be availed with Aadhaar-based authentication -- There no need to go to the RTO office; it will reduce footfall at RTO and increase efficiency of the RTO officers; it will end corrupt practices by middlemen and brokers; and the Government is committed to transparent, timebound and corruption-free practices. This is a first-of-its-kind move. यह रिवाल्यूशनरी चेंज हुआ। अब घर में बैठकर काम हो सकता है। मैं इसकी लिस्ट पढ़कर बता रहा हूं – लर्निंग लाइसेंस, घर में बैठकर एप्लाई करो मिल जाएगा। The list includes renewal of driving licence for which test of competence to drive is not required; duplicate driving licence; change of address in driving licence and certificate of registration; issue of international driving permit; surrender of class of vehicle from licence; application for temporary registration of motor vehicle; application for registration of motor vehicle with fully built body; application for issue of duplicate certificate of registration; application for grant of NOC for certificate of registration; notice of transfer of ownership of motor vehicle; application for transfer of ownership of motor vehicle; intimation of change of address in certificate of registration;

application for registration for driver training from accredited Driver Training Centre; application for registration of motor vehicle of diplomatic officer; application for assignment of fresh registration mark of motor vehicle of diplomatic officer; endorsement of hire-purchase agreement; and termination of hire-purchase agreement.

We have written to all the States to implement at the earliest. इसमें एक और अच्छा काम किया है। इसकी वजह से आज पूरा आरटीओ मुझसे नाराज है। आरटीओ ऑफिस में किसी को जाना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा काम, जिसका करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी गाड़ी के पेपर्स, अब आपके मोबाइल में है। हमने एक सिक्योरिटी इलेक्ट्रोनिक लॉकर बनाया है, उसमें रख सकते हैं। जब पुलिस आपको कहीं रोकती है, तो आप अपना मोबाइल फोन निकालकर लाइसेंस दिखा सकते हैं। अब उसको भी साथ रखने की जरूरत नहीं है। हमने ईज ऑफ बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया है। इसमें एनआईसी ने हमें डायरेक्टली सर्पोट किया है और स्टेट को भी कर रहे हैं। बाकी सेन्ट्रलाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से काम हो रहे हैं।

डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन, यह एक बहुत बड़ी बात है। इसमें आपने सहयोग किया है। नई गाड़ी खरीदने के बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं करता है। नियम ऐसा था कि डीलर वह गाड़ी आरटीओ ऑफिस में लेकर जाएगा, वह नम्बर देगा, तब गाड़ी वापस आएगी। यह सब क्यों हो रहा था, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि डीलर ही रजिस्ट्रेशन ई-मेल से भेज देगा और इंटरनेट के साथ बताएगा। वही नम्बर भेजेगा, ठप्पा लगाएगा और हो जाएगा। अब आरटीओ भेजने की जरूरत नहीं है। प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईज ऑफ बिजनेस में इतने बड़े परिमाण पर रिफॉर्म्स हुए हैं। मुझे लगता है कि एक बार आप सभी सदस्यों को अलग-अलग डिपार्टमेंट में जो चेंजेज हुए हैं, उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भी, यदि आपको लगता है कि जनता को तकलीफ़ होती है, तो आप हमें बताइए। हम पूरी तरह से आपको इसमें मदद करेंगे। हमने नेशनल परमिट को भी इंटरनेट पर डिजिटल कर दिया है। अब परमिट लेने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। जो हिस्सा फीस का मिलता है,

उसको हम अलग-अलग राज्यों में बंटवा देते हैं। चाहे ट्रक वाले हों, प्राइवेट बस वाले हों, परमिट लेना, चुनाव जीतने से भी कठिन काम था। पर, अब यह पूरी तरह से डिजिटेलाइज हो गया है। यह ईज ऑफ बिजनेस ही हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हर विभाग में यह काम बहुत अच्छा हुआ है।

माननीय सभापति: आपने जो प्रश्न पूछा था, क्या उस पर आपकी शंका दूर हुई?

श्री बिद्युत बरन महतो: माननीय मंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जनप्रिय एवं यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता प्रशासन को सरल, सुगम, भ्रष्टाचार रहित बनाना है। माननीय मंत्री जी आपकी दूरदर्शिता और कार्यकुशलता के फलस्वरूप सरकार आधार प्रमाणीकरण आधारित सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है। भारतीय सड़क को पर्याप्त सुगम और निर्बाध सुविधा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं। परन्तु, सड़क, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं टोल बूथों की संख्या बहुत अधिक है, जहां वाहनों को कतारों में लगना पड़ता है। इससे ईंधन और धन की बर्बादी होती है, साथ ही साथ, प्रदूषण भी बढ़ता है।

अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार टोल बूथों की संख्या कम करने तथा टोल टैक्स घटाने के लिए कौन-सी नीति बना रही है, ताकि, पर्यावरण की रक्षा हो, ईंधन की बचत हो तथा आम आदमी की जेब पर कम बोझ पड़े?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सभापति महोदय, वैसे, कोविड के काल में सभी जगह नुकसान हो रहा है। अभी भी हमारे कुछ हाईवेज किसान आंदोलन के कारण ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। पिछले साल हमारे टोल की इन्कम 24,000 करोड़ रुपये थी। इस साल कोविड और आंदोलन को देखकर मुझे लगा कि इनकम 10,000 करोड कम होगी और वह 14,000 करोड़ पर आएगी। लेकिन, हमने आप सबके सहयोग से फॉस्ट टैग सिस्टम लागू किया। अभी 93 परसेंट लोगों ने फॉस्ट टैग ले लिया है। जयपुर जाने के दौरान खेड़की टोल नाका के पास लोगों को आधा-आधा घंटा रूकना पड़ता था। अब हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि कौन व्यक्ति किस टोल नाके के पास कितने मिनट रूका है, उसका जवाब मैं एक मिनट में दे

सकता हूं। इसके लिए, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उसको चेयरमैन, एनएचएआई और मैं स्वयं मॉनिटर करता हूं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब कहीं भी तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। पूरी तरह से फॉस्ट टैग सिस्टम हो गया है। अब हमारी टोल इन्कम कम होने के बजाय, कोविड और किसान आंदोलन होने के बाद भी 10,000 करोड़ रुपये बढ़ी है। अब हमारी इन्कम 34,000 करोड़ रुपये हो गयी है।

जो फास्टैग है, अभी यह 93 प्रतिशत ही हुआ है। कुछ राज्यों में लोग डबल टोल दे रहे हैं, लेकिन वे फास्टैग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपको उसका कारण मालूम है। कोई इन्कम टैक्स की चोरी करता है, कोई जीएसटी की चोरी करता है, कोई इधर का माल उधर करता है, वह रजिस्टर नहीं होना चाहता है। लेकिन अभी मैंने कहा है कि पुलिस और कलेक्टर को आर्डर दो, उनको अरेस्ट करो और उन पर कार्रवाई करो। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में इस देश में नंबर दो का धंधा नहीं चलेगा। उन पर भी कार्रवाई होगी और यह 100 प्रतिशत होगा।

कल ही मेरे यहां एक मीटिंग है। अब हम इसके बाद जीपीएस सिस्टम टोल नाके कर रहे हैं। हम टोल नाकों को खत्म कर देंगे। नई गाड़ियों में तो जीपीएस लगकर आता है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के लिए हम अपनी तरफ से जीपीएस खरीदकर उनमें लगा देंगे। जैसे फास्टैग है। वह जीपीएस सैटेलाइट से जुड़ा होगा। आप जहां से एंट्री करेंगे, वहां पर रजिस्टर हो जाएंगे और आप जहां से बाहर निकलेंगे, वहां भी रजिस्टर हो जाएंगे। आपको उतना ही टोल देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं और यह बात सही भी है कि शहर के बाहर टोल नाका खड़ा किया गया है। वह पुरानी सरकार के समय किया गया था, हम उनको नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्षतिपूर्ति मांगते हैं। अब वह बीमारी भी खत्म हो जाएगी। ट्रैफिक पूरी तरह से ट्रांसपैरेन्ट हो जाएगा और एक सिस्टम होगा।

एक सम्माननीय सदस्य ने जमशेदपुर की बात बताई थी। हम लोग चेन्नई और पुणे में एक नया सिस्टम कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक अच्छे डिजाइनर से कहा है कि सबसे पहले नीचे 6 या 8 लेन की एक रोड होगी, उसके ऊपर फ्लाईओवर होगा, उस फ्लाईओवर के ऊपर एक और फ्लाईओवर होगा, फिर उसके ऊपर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। हमने ऐसा चेन्नई

और पुणे के लिए डिजाइन किया है। हमने जमशेदपुर के लिए भी नीचे रोड, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर होगा, क्योंकि वहां पीएसयूज़ काफी ज्यादा हैं। हम शेखावत जी के भी संसदीय क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं। अब केवल बिल्डिंग ही नहीं बनेगी, बल्कि फ्लाईओवर भी डबल डेकर और तीन लेयर के बनेंगे। हमारे यहां नागपुर में रोड, रोड के ऊपर फ्लाईओवर और उस फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो चलेगी। यह देश का पहला डिजाइन होगा, जिसे काफी लोग देखेंगे। उसको काफी लोगों ने पसंद भी किया है और हम आगे इस पर काम करेंगे।

माननीय सभापति : श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक **-** उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 424. **श्री सुनील बाबूराव मेंढे**।

(Q. 424)

श्री सुनील बाबूराव मेंढे: सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो कॉलेज गोइंग स्टूडेन्ट्स हैं, जिनको राष्ट्रीय सेवा योजना में लगाया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनके माध्यम से सोशल वर्क किया जाता है।

माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जिससे मुझे भी पता चला है कि खासकर हमारे महाराष्ट्र में सवा तीन लाख बच्चे इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और वे सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ है कि इन सवा तीन लाख बच्चों में से करीब-करीब 95,000 बच्चों ने कोविड पैनडेमिक कंडीशन में 27 लाख मास्क बनाए हैं, जो उस समय कोविड पैनडेमिक कंडीशन की सबसे बडी नीड थी, वह पूरी की है। उनको ट्रेनिंग देकर यह काम पूरा किया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी और खासकर उन बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से पहला सवाल यह है कि हमारे देश में कुल मिलाकर 35 लाख बच्चे इस योजना के तहत काम कर रहे हैं। उनमें से खाली सवा तीन लाख बच्चे हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से ही हैं। क्या हम लोग इस संख्या को बढ़ाने के बारे में प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस संख्या में अधिक वृद्धि हो सके तथा और भी अधिक मात्रा में बच्चे इसमें सहभागिता करके हमारे देश को सेवा प्रदान कर सकें?

श्री किरेन रिजीजू : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के बारे में जो जिक्र किया है, मैंने उसका जवाब भी दिया है। अभी लगभग 37 लाख के आसपास हमारे वॉलंटियर्स हैं। इसमें महाराष्ट्र का शेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि वह एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वहां छात्रों की जनखंख्या भी ज्यादा है। हम चाहते हैं कि इस संख्या को किसी भी तरह से बढ़ाया जाए। जब कोविड शुरू हुआ था, तब हमने एक टारगेट रखा था कि हमारे देश में एक करोड़ वॉलंटियर्स तैयार होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति या कोई इमरजेन्सी सिचुएशन आ जाए, तो हमारे देश का जो यूथ वॉलंटियर्स है, वह मिनिमम एक करोड़ होना चाहिए।

हमारे पास इस वक्त लगभग 70 लाख यूथ वॉलंटियर्स मौजूद हैं और हमारे द्वारा 1 करोड़ की संख्या के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। कोविड के चलते जो बजटरी एलोकेशन्स हैं या कार्यक्रम करने के लिए जो बजट होता है, उस बजट में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हम वॉलंटियर्स की संख्या को नहीं बढ़ा पाए हैं। मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को अच्छे से सुना है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे देश में एक करोड़ यूथ वॉलंटियर्स तैयार हो जाएँ, जिसमें महाराष्ट्र से कम से कम पांच लाख वॉलंटियर्स होने चाहिए।

श्री सुनील बाबूराव मेंढे : सभापति महोदय**,** मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब यह पेंडेमिक सिचुएशन आई और हमने देखा कि काफी मात्रा में वॉलंटियर्स की जरूरत है**,** उस समय मेरे खुद के स्कूल के बच्चे जो आठवीं से दसवीं क्लास के बीच में हैं**,** उनके मेरे पास काफी फोन आ रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या हम भी इसमें अपनी कुछ सेवा दे सकते हैं? इस माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आठवीं से दसवीं क्लास के बच्चों की उम्र लगभग 13 से 15 साल के बीच में होती है तो अगर ऐसे बच्चे भी इस योजना का लाभ लें और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे भी हमारे देश में सेवा देने के लायक हो सकते हैं। यह सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार ऐसा विचार कर रही है?

श्री किरेन रिजीजू : सर, अभी हम दो कैटेगरीज़ में नेशनल सर्विस स्कीम चला रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी लेवल पर चल रही है, जो प्रोग्राम कॉर्डिनेटर के माध्यम से चलाई जाती है। दूसरी, +2 काउंसिल लेवल और कॉलेज प्रोग्राम ऑफिसर के माध्यम से चलाई जाती है। अभी हमारे पास मैट्रिक से नीचे की योजना नहीं है, लेकिन हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और भी कार्यक्रम चलते हैं, जैसे नेहरू युवा केन्द्र संगठन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है। इसके माध्यम से हम इन्हें अलग-अलग स्कीम्स में जोड़ सकते हैं। माननीय सदस्य ने कोविड के समय वॉलंटियर्स के काम का जिक्र किया है। मेरे पास उनकी सूची है और जब आप सुनेंगे तो आपको गर्व होगा। वॉलंटियरिज्म का कांसेप्ट इंडिया को काफी आगे लेकर गया है। देशभर में बहुत ही सीमित साधन के साथ, मास्क बनाने से लेकर लोगों को सहायता देने और उनमें अवेयरनेस क्रियेट करने तक हमारे युवा साथियों ने जो काम किया है, वह बहुत

सराहनीय है। इसके साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो आह्वान किया, उसके जरिए हमारे देश के सभी कोविड वॉरियर्स के साथ यूथ वॉलंटियर्स जुड़े रहे। आज मैं इस सदन के माध्यम से देश के सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री विनायक भाउराव राऊत : सभापति महोदय, धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से देश के करोड़ो युवक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करते हैं। मैं मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें महाराष्ट्र से कम से कम पांच लाख बच्चें शामिल होने की अपेक्षा की है। निश्चित ही अभी सवा तीन लाख है तो पांच लाख होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो बच्चें शामिल होते हैं और जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि स्कूल और कॉलेज के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस योजना के अंदर शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए इस योजना का ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की भी आवश्यकता है। इसके साथ-साथ जो बच्चे इस योजना में सोशल वर्क करने के तौर पर शामिल होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। क्या इस योजना में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स या बच्चों को ट्रांसपोर्ट के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है? इसके साथ-साथ मेरा एक और सुझाव है कि आप इन स्वयं सेवकों को बढ़ावा देते हैं तो इसमें जो लास्ट कैडर होता है, उसके अंतर्गत पूरे स्टेट में केवल 30 अवार्ड दिए जाते हैं। उनकी संख्या करीब सवा तीन लाख होती है तो सिर्फ 30 पुरस्कार बहुत कम हैं। अगर आप पुरस्कार में बढ़ोतरी करेंगे तो वे और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। मंत्री जी का इस बारे में क्या विचार है?

श्री किरेन रिजीजू: माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आखिरी वाले प्वाइंट को पहले बता देता हूं। हम एक तो यूनिट के हिसाब से अवार्ड देते हैं और 30 इंडिविजुअल्स को देते हैं। हमने इसकी प्राइज मनी भी बढ़वाई है। पिछले साल हमने इसको बढ़ा दिया था। अभी हम यूनिट्स को फर्स्ट प्राइज के रूप में **5** लाख रुपये देते हैं और सेकण्ड प्राइज के रूप में 3 लाख रुपये देते हैं। जो 30 वालंटियर्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें हम एक वालंटियर को 1 लाख रुपये देते हैं। आज ही सुबह

मैंने अपने सेक्रेटरी और ऑफिसर्स को कहा है कि हम इसके दायरे को थोड़ा बढ़ाएंगे और इन अवार्ड्स को हम फर्स्ट, सेकण्ड और थर्ड – तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आने वाले साल में मैं चाहता हूं कि इसका दायरा भी बढ़े और आपने जो सुझाव दिया है कि इस संख्या को 30 से बढ़ाया जाए, उस पर भी हम जरूर विचार करेंगे। अगर मैं अभी घोषणा कर दूंगा और अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं हुए तो हम उसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सुझाव को हम जरूर मानें।

सर, मैं एक इन्फार्मेशन देना चाहता हूं कि हम अपने वालंटियर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना चाहते हैं और आज देश में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके साथ हमने एमओयू किए हुए हैं, एग्रीमेंट किया है, वे हमारे यूथ वालंटियर्स को ट्रेनिंग देंगे। इस बार हमारे यूथ वालंटियर्स ने, खासकर यह सवाल एनएसएस के बारे में है, बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे ब्लड डोनेशन में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दी है, वह देश में नम्बर-1 है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा ट्री प्लांटेशन भी हमारे एनएसएस वालंटियर्स ने किया है। इसी प्रकार से पूरे देश में सबसे ज्यादा आरोग्य सेतु एप डाउनलोड भी हमारे एनएसएस वालंटियर्स ने करवाया है। इनके कामों की इतनी लम्बी सूची है कि अगर मैं उनकी गिनती करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं उनके कामों की प्रशंसा करना चाहता हूं।

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या 425. **श्री रविन्दर कुशवाहा** ।

(Q. 425)

श्री रविन्दर कुशवाहा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यमुना नदी तट के विकास के साथ-साथ, नदियों का भी विकास होना चाहिए, उनके तटबन्ध अच्छे होने चाहिए। इसी के साथ, हमारे यहां सरयू नदी है। हमारे देवरिया जिले में सरयू नदी के किनारे बरहज नाम का स्थान है, जहां पर पुराने जमाने में बड़े-बड़े जलपोतों के द्वारा व्यापार होता था और बरहज बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। माननीय मंत्री जी ने सदन में भी घोषणा की थी कि हल्दिया से लेकर हावड़ा तक हम नए जलमार्ग का निर्माण कर रहे हैं। उसी से संबंधित वह जलमार्ग हमारे बलिया से होकर गुजरता है और बलिया से देवरिया में सरयू नदी के तट पर स्थित बरहज, जो एक व्यापारिक केन्द्र है, लगा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या बरहज को जलमार्ग से जोड़कर, पहले की तरह उसे व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है?

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरयू नदी के घाटों को विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना बनी है और उस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्लान बना रही है। जैसे ही उसके बारे में कोई कंक्रीट जानकारी मिलेगी, तब उसके आगे की कार्यवाही होगी।

श्री रविन्दर कुशवाहा: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देवरिया जिले में, सरयू नदी के किनारे पर मईल नामक स्थान पर बहुत बड़े सन्त देवरहा बाबा का आश्रम था। देवरहा बाबा के बहुत बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु लोग हैं। हर साल उनके आश्रम पर, उनके दिवंगत होने के बाद भी, वे लोग पूजा करने आते हैं। वह स्थान नदी के किनारे ही है। क्या मईल नामक स्थान पर पर्यटन स्थल के रूप में, श्रद्धा के केन्द्र देवरहा बाबा के दर्शन-पूजन के लिए नदी के तट पर सरकार कोई व्यवस्था कर सकती है?

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, लेकिन जो प्रश्न है, वह पर्यटन विभाग से संबंधित है। इस बारे में वह विभाग ही कोई निर्णय ले सकता है।

माननीय सभापति : श्री रवि किशन जी – उपस्थित नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: आदरणीय सभापति जी, मेरठ से काली नदी होकर गुजरती है, जो सहारनपुर से चलती है। यह कन्नौज में गंगा में जाकर मिल जाती है। यह गंगा की सहायक नदी है। यह देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। मेरठ के निकट 50 गांव पानी की दृष्टि से इतने विषाक्त हो गए हैं कि वहां पर हेपेटाइटिस बी और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। इसे पानी के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए मार्च, 2018 में 682 करोड़ रुपये की योजना 'नमामि गंगे योजना' में मंजूर हुई थी, लेकिन उसका काम बहुत धीरे चल रहा है। वह नदी अभी भी प्रदूषित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि इस काम की गति को बढ़ायें और जिस प्रकार से गंगा की सहायक नदी होने के नाते, यह विषय गंगा के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको कब तब पूरा करने की सरकार की योजना है?

श्री रतन लाल कटारिया : माननीय सभापति जी, जो मूल प्रश्न है, वह यमुना नदी से संबंधित है। मैं इस बारे में माननीय सदस्य को इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जहां तक यमुना के बारे में प्रश्न है, हम वृंदावन में 177 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना बना रहे हैं, जिससे यमुना के पानी में सुधार आ सके।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे एक्चुअली यमुना पर प्रश्न पूछना था, क्योंकि दिल्ली में यमुना की जो हालत है, वह आप सबके सामने ही है । हो सकता है कि अभी नियमों में कंफ्यूजन खत्म हो गया है तो अब यमुना की स्थिति भी बेहतर होगी, लेकिन जो मेरा प्रश्न है, वह जलमार्ग से संबंधित है। ऐलेप्पी के अंदर पेपर पर एक जलमार्ग की योजना बनाई हुई है। हमने इसी हफ्ते की शुरूआत में देखा कि वहां पर हायसिंथ लगा हुआ है और जलमार्ग के नाम पर वेंबनाड लेक में कोई काम नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, इस सदन को आश्वासन देंगे कि केरल के अंदर जो जलमार्ग की परियोजना है, क्या उसकी स्थिति में अधिक काम करने का प्रयास कर रहे हैं?

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अदंर यमुना को लेकर 800 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य कर रही है। यमुना के सौंदर्यीकरण को लेकर, उसकी ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए 10 प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है।

डॉ. सत्यपाल सिंह: सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न में यह लिखा है कि जो यमुना के साथ-साथ बहने वाली दूसरी नदिया हैं, उनमें तीन नदियां – काली, कृष्णा और हिंडन ऐसी हैं, जो यमुना में मिलती हैं। वे नदियां छ: जिलों को परेशान कर रही हैं। उनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और नोयडा हैं। इन नदियों से 108 गांव प्रदूषित हैं। इससे लोगों में कैंसर बढ़ रहा है, अलग-अलग तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं और इसमें एनजीटी का आदेश भी है। सरकार ने बागपत में यमुना के ऊपर एक वॉटर फ्रंट की घोषणा की थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीन नदियों का प्रदूषण कब तक दूर होगा और बागपत में वॉटर फ्रंट कब तक आएगा?

श्री रतन लाल कटारिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने काली नदी के लिए एक विशेष परियोजना के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसको लेकर एक परियोजना मंजूर की गई है। विश्व बैंक इस परियोजना में सहायता करेगा। इस परियोजना को वर्ष 2022 तक पूरा करने का हमारा लक्ष्य है।

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या 426. **डॉ उमेश जी. जाधव** ।

(Q. 426)

DR. UMESH G. JADAV: Thank you, Chairperson Sir. Currently, Kalaburagi is having a ring road, namely NH 50 and NH 150E, which has become the lifeline of Kalaburagi city. Since the city has outgrown beyond the existing ring road at an alarming rate, the entire traffic of NH 150E, NH 50 and NH 150 has to travel on the existing ring road along with the local city traffic, which results in heavy traffic congestion and poor riding quality.

During peak hours, the traffic intensity of the existing ring road is about 45,000 PCU. Many accidents are taking place on this road.

The work on this ring road was allotted to L&T but they have not completed the work of service road at NH-50 and NH-150E. The major junction has also not yet been created. In the current scenario, construction of mini flyover at Ram Mandir Cross, Humnabad Cross and Mehboob Nagar is very much essential.

I would like to know from the hon. Minister the measures taken in this regard to complete this work at the earliest.

श्री नितिन जयराम गडकरी : सर, सम्माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है कि वह 45 हजार पीसीयूज की ट्रैफिक है। इस रोड की वाइंडिंग करने और फ्लाईओवर बनाने के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से उसको बनाने के बाद इस समस्या का समाधान होगा।

HON. CHAIRPERSON: You can ask a short second supplementary.

DR. UMESH G. JADAV: Sir, my second question is related to the first supplementary, which is very much important and is the need of hour for my parliamentary constituency. In this regard I have met the hon. Minister many

times. The new Kalaburagi bypass is required for safe, smooth and congestion free movement of traffic.

The proposed length of bypass is 41.43 km, starting at junction with NH-150E and ends at junction with NH-50. The proposed bypass is four-lane with paved shoulder carriageway. The alignment connecting NH-150E and NH-50 *via* NH-150 has already been approved by the Ministry on 14.02.2017 and 3 (a) notification published in the Gazette on 19.01.2019. Declaration of NH to this proposed bypass is awaited from the Ministry. The land acquisition cost in the current annual plan also needs to be approved.

I would like to know from the hon. Minister whether any time frame has been set to complete this project. If not, I would humbly request the Minister to give NH Number to the above-mentioned bypass for the overall development of my Parliamentary Constituency.

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, देश के केई क्षेत्रों में बाईपास की काफी मांग है। इसके बारे में डिपार्टमेंट ने एक नीति तय की है कि जहां पर भी बाईपास बनाएंगे, वहां जो लैंड एक्विजिशन होगा, उसका 50 प्रतिशत कंट्रिब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट देगा। यह स्कीम आगे नहीं जा पा रही है, क्योंकि राज्य सरकार 50 प्रतिशत कंट्रिब्यूशन देने की स्थिति में नहीं है। मैंने उसमें ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया है कि बाईपास बनाने के लिए जो स्टील और सीमेंट लगता है, उसमें स्टेट की जो जीएसटी लगती है, उसे एग्जेम्प्ट करें और रोड बनाने के लिए जो मैटीरियल यूज किया जाता है, उसे रॉयल्टी फ्री कर दीजिए तो कम से कम आपका यह कंट्रीब्यूशन पकड़ा जाएगा। हम लोग राज्य सरकार की सहमति के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे इस प्रपोजल पर आ कर हम से डिसकस करके यह काम भी करेंगे, तो हम मार्ग भी निकालेंगे और इस नीति में बदलाव करेंगे। वर्तमान स्थिति में राज्य की तरफ से बाईपास के लिए 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देना आवश्यक है। इसके कारण ये काम रूके हुए हैं।

मैं आदरणीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि उनके राज्य सरकार की ओर से अगर 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देना है, तो उसकी मंजूरी ला कर दीजिए। अगर यह नहीं होता है, उसमें भी अड़चन है, तो मैंने जो सॉल्यूशन बताया है, आप उसके लिए राज्य सरकार की कमिटमेंट लेकर आइए। अगर यह आएगा कि हम आपके लैंड एक्विजिशन का काम लेकर जाएंगे और बाईपास का काम शुरू करेंगे।

HON. CHAIRPERSON: Question No. 427

Shri Girish Bhalchandra Bapat.

(Q. 427)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि देश में बसावटों की संख्या और इसमें 'हर घर जल' की जो योजना है, खास कर ग्रामीण इलाके में जब एक बसावट रहती है, तो जानवरों को पानी पीने और लोगों को पानी देने के लिए यह बहुत उपयुक्त है।

आपने इस प्रश्न का उत्तर सविस्तार दिया है। लेकिन जो वॉटर लेवल बढ़ना चाहिए और दूषित पानी का पर्कुलेशन होता है, क्या इसके लिए स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा किसी योजना का इंप्लीमेंटेशन होगा, जिससे हर घर जल के लिए सोर्स ऑफ वॉटर हो और लोगों को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो?

श्री रतन लाल कटारिया: माननीय सभापति महोदय, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले वर्ष लाल किले के प्राचीर से इस देश में जल जीवन मिशन शुरू किया था। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को नल से जल देने की योजना बनी है। माननीय सदस्य ने जो वॉटर कंटेनमेशन की बात की है, मैं उसके बार में यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 से नेशनल वॉटर क्वॉलिटी सबमिशन कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके अनुसार देश में 27,544 आर्सेनिक और फ्लोराइड वाले हैबिटेशन पाई गई थी। इसके बाद उस पर कार्ययोजना शुरू हुई थी। इसके बाद 1,369 ऐसी हैबिटेशन ही बची थी, जिनमें आर्सेनिक और फ्लोराइड पाया गया था।

वर्तमान में जब से जल-जीवन मिशन शुरु हुआ है, उसे देखते हुए फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, सेलेनिटी, नाइट्रेट, हैवी मेटल्स इन्हें मिलाकर आज देश में 48,169 रुरल हैबिटेशन ऐसी हैं, जो कंटेमिनिशेन से प्रभावित हैं। इनमें से 2,637 में कम्युनिटी वॉटर प्योरिफिकेशन सिस्टम डेवलेप करके ठीक करने की कोशिश की है। इसके लिए 4,50,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशीक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण ले कर, जनता को जागरुक करेंगी।

HON. CHAIRPERSON: Now, the Question Hour is over.

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 428 to 440 and

Unstarred Question Nos. 4831 to 5060) (Pages 47 to 756)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library

12.00 hrs

…(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, मैं दो बातें पूछना चाहता हूं, उसके बारे में आप बताइए, बजट सेशन चल रहा है। …(व्यवधान) सारा देश इसे देख रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर जी से वेस्ट बंगाल की रैली में जाकर मिलें? …(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि इस बजट में सारे बिल पास हुए हैं, लेकिन गरीब के तेल के बारे में, चूल्हे के बारे में, सिलेंडर के बारे में, छत के बारे में, उन्हें एक बार भी सस्ता करने की बात नहीं हुई है।…(व्यवधान) हमने सारे बिल पास किए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**) : आप गलत बोल रहे हैं। प्रधान मंत्री जी हाऊस में भी आए थे।…(व्यवधान) आप प्रधान मंत्री जी के बारे में…(व्यवधान) क्या करते हैं? …(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह: आप प्रधान मंत्री जी के दर्शन करवा दीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: प्रधान मंत्री जी, हाऊस में आए थे।…(व्यवधान) आप प्रधान मंत्री जी के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। वे मिलने के लिए तैयार रहते हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Papers to be laid on the Table. …(*Interruptions*)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. CHAIRPERSON: Now, Papers to be laid on the Table. Item nos. 2 to 5, hon. Minister, Shri Arjun Ram Meghwal Ji. …(*Interruptions*) पेपर्स लेड हो रहे हैं, प्लीज।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदय, श्री किरेन रिजीजू जी की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4259/17/21]

(3) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library,See No. LT4260/17/21]

(5) (एक) दादरा और नागर हवेली वक्फ़ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा और नागर हवेली वक्फ़ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library,See No. LT4261/17/21]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library,See No. LT4262/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदय, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library,See No. LT4263/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदय, श्री हरदीप सिंह पुरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library,See No. LT4264/17/21]

(ख) (एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library,See No. LT4265/17/21]

(ग) (एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library,See No. LT4266/17/21]

(3) (एक) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library,See No. LT4267/17/21]

(5) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14(क) के अंतर्गत मानवरहित वायुयान प्रणाली नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library,See No. LT4268/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदय, श्री मनसुख मांडविया की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library,See No. LT4269/17/21]

(3) पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अंतर्गत पोत पुर्नचक्रण नियम, 2021 जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 20 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library,See No. LT4270/17/21]

HON. CHAIRPERSON: Now, Item nos. 6 and 6A, Secretary General.

12.03 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

(i) **SECRETARY GENERAL:** Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 2021, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd March, 2021 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 24th March, 2021 agreed without any amendment to the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 2021."

12.03 ½ hrs

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

HON. CHAIRPERSON: The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in their Fourth Report presented to the House on 24th March, 2021 have recommended that leave of absence from the sittings of the House be granted to the following Members for the periods mentioned against each:

1.	Shri Sanjay Shamrao Dhotre (Minister of State)	08.03.2021 to 04.04.2021
2.	Gen. (Retd.) Vijay Kumar Singh (Minister of State)	10.03.2021 to 08.04.2021
3.	Shri Abdul Khaleque	11.02.2021 to 13.02.2021 & 08.03.2021 to 06.04.2021
4.	Shri Anant Kumar Hegde	08.03.2021 to 05.04.2021
5.	Shri Y. S. Avinash Reddy	04.03.2020 to 23.03.2020 14.09.2020 to 23.09.2020 29.01.2021 to 13.02.2021 & 08.03.2021 to 18.03.2021

6. Shri Sisir Kumar Adhikari 29.01.2021 to 13.02.2021
&
08.03.2021 to 08.04.2021

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The leave is granted. The Members will be informed accordingly.

12.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 278th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways*

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI) : Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 278th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Road Transport & Highways.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4251/17/21.

12.04 ½

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on 'General Defence Budget, BRO, ICG, MES, DGDE, DPSUs, Welfare of Ex-Servicemen, Defence Pension and ECHS (Demand No. 19 & 22)' pertaining to the Ministry of Defence*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on ‘General Defence Budget, BRO, ICG, MES, DGDE, DPSUs, Welfare of Ex-Servicemen, Defence Pension and ECHS (demand no. 19 and 22)’ pertaining to the Ministry of Defence.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4252/17/21

12.05 hrs

(iii)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Energy on 'Energy Conservation' pertaining to the Ministry of Power*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 7th Report of the Standing Committee on 'Energy Conservation' pertaining to the Ministry of Power.

(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Energy on 'National Electricity Policy-A review' pertaining to the Ministry of Power*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH) : Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Energy on 'National Electricity Policy-A review' pertaining to the Ministry of Power.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 4253/17/21 and 4254/17/21 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Energy on 'Evaluation of Role, Performance and functioning of Power Exchange' pertaining to the Ministry of Power*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH) : Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Energy on 'Evaluation of Role, Performance and functioning of Power Exchange' pertaining to the Ministry of Power.

(d) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Energy on 'Functioning of Central Electricity Regulatory Commission' pertaining to the Ministry of Power*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH) : Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Energy on 'Functioning of Central Electricity Regulatory Commission' pertaining to the Ministry of Power.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 4255/17/21 and 4256/17/21 respectively.

12.06 hrs

(iv) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 138th Report of the Standing Committee on Commerce on 'Activities and Functioning of Spices Board' pertaining to the Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 138th Report of the Standing Committee on Commerce on 'Activities and Functioning of Spices Board' pertaining to the Ministry of Commerce and Industry.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 150th Report of the Standing Committee on Commerce on "Export of Organic Products: Challenges and Opportunities" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 150th Report of the Standing Committee on Commerce on "Export of Organic Products: Challenges and Opportunities" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 4257/17/21 and 4258/17/21 respectively.

12.07 hrs

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON PERSONAL DATA PROTECTION BILL,2019 – EXTENSION OF TIME

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move:

"That this House do extend upto the first week of Monsoon Session 2021 of Parliament the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019".

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That this House do extend upto the first week of Monsoon Session 2021 of Parliament the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019".

The motion was adopted.

12.08 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise mattes under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

(i) Need to set up a Horticulture University in Dhar district, Madhya Pradesh

श्री छतरसिंह दरबार (धार): मध्य प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र धार एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहां के लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत खेती एवं पशुपालन है। मध्य प्रदेश के अन्य आदिवासी जिलों झाबुआ, खरगोन, बड़वानी और खंडवा में स्थित धार जिले की मनावर तहसील में एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में फलों और फूलों की खेती करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में नर्मदा परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना तथा माही परियोजना के चलते जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता यहां के किसानों के लिए एक वरदान है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र के उन्नतिशील किसानों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कृपा करें।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to extend intercity train (Train No. 02529) upto Bhatni Junction Railway Station in Deoria district, Uttar Pradesh

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश की पूर्वी दिशा का सबसे पिछड़ा और अंतिम जिला है। देवरिया जिला मुख्यालय से गोरखपुर की दूरी 50 कि.मी. है। गोरखपुर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक यात्रियों कि सुविधा के लिए प्रतिदिन एक इंटर सिटी ट्रेन (02529) जाती है और शाम को (02530) वापस आती है। इससे गोरखपुर और लखनऊ के बीच के लगभग 7 जिलों की जनता इस सुविधा से लाभान्वित होती है और अपने कार्यों से सम्बंधित इस सुविधा का लाभ उठाती है केवल 1 जिला देवरिया इस सुविधा से वंचित रह जाता है।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस इंटर सिटी ट्रेन (02529) को देवरिया जिला के भटनी जंक्शन जो बिहार का बार्डर है, तक बढ़ाया जाये जिसकी दूरी गोरखपुर जिले से 70 कि.मी. है। जिससे इसकी सुविधा देवरिया के लोगों को भी मिल सके जो इस से वंचित रह जाते है। लखनऊ राजधानी से प्रशासनिक तथा चिकित्सक कार्यों से जाने वाले लोग जो इस सुविधा से वंचित रह जाते है, उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

(iii) Regarding boosting of tourism and employment opportunities in Jalgaon

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Jalgaon is a city of historical importance and several places of religious and historical importance are located here. Maheshwara Temple, Chandika Devi Temple, Nagarjun Temple and Mudhai Devi Temple have been included under the Central List of Protected Monuments of Archaelogical Survey of India and is visited by devotes from across the country. As these temples date back to 11th century, there is a need for regular maintenance to preserve their origin. These temples currently are in a dilapidated condition and need urgent conservation. I request the Government to prepare the Detailed Project report for conservation of these monuments and ensure that the restoration work is carried out in a time bound manner by Archaeological Survey of India. A comprehensive strategy should also be conceptualized to develop the adjoining 100 metres area around these temples to boost tourism in Jalgaon and create employment opportunities.

(iv) Need to resume operation of Weaving Mill in Sandila Tehsil in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र में संडीला तहसील में कताई की मिल थी, जो पिछले काफी समय से बंद पड़ी हुई है। इस मिल के अभी तक चालू न होने के कारण श्रमिक बेकार हो गए हैं और उनकी जीविका का सहारा भी छूट गया है तथा उनके परिवार अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा इस कताई मिल को पुनः चालू करवाये जाने हेतु विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

मेरा अनुरोध है कि मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत संडीला में बंद पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने हेतु विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर पुनः चालू किया जाए और यदि बंद पड़ी इस कताई मिल को पुनः चलाना संभव नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में इस मिल की रिक्त पड़ी भूमि को डिफेंस कॉरिडोर में शामिल किया जाए अथवा इस भूमि को इण्डस्ट्री स्थापित किए जाने हेतु आवंटित किया जाए, ताकि रिक्त पड़ी भूमि विकसित हो सके एवं स्थानीय युवकों को रोजगार सुलभ हो सके।

(v) Regarding providing facilities to retired personnel of paramilitary forces at par with ex-servicemen

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): अर्धसैनिक बल के जवान (पैरामिलिट्री फोर्सेस) पूरी निष्ठा और देशभक्ति के साथ देश की सरहदों की रक्षा व आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में अपनी अहम भूमिका अदा करते है। प्राकृतिक आपदायें बाढ़-भूकंप के समय व आवश्यकता पडने पर राज्यों में कानून व्यवस्था बनाये रखने सहित दंगाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों का सराहनीय योगदान किसी से भी छिपा नहीं है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 23 नवंबर 2012 को सभी राज्य सरकारों को मेमोरेंडम जारी कर अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्त सैनिकों की तरह ही सुविधायें प्रदान करने के लिये कहा था। लेकिन वर्तमान में कुछ ही राज्य सरकारों द्वारा यह सुविधा प्रदान की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को देखते हुये शेष बचे राज्यों में भी सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों के जवानों को सेवानिवृत्त सैनिकों की तरह ही सुविधायें मिल सकें इस हेतु भी प्रयास करने चाहिये।

(vi) Regarding conversion of Uttarkashi-Kamad-Anyarkhal-Burhakedar-Ghansali-Mayali-Tilwara road in Uttarakhand as all weather National Highway

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तराखंड के सीमांत जपनद उत्तरकाशी की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उत्तरकाशी से कम दूरी, सरल-सुगम एंव पौराणिक बूढाकेदार मंदिर को जोड़ने वाला, उत्तरकाशी कमद-अंयारकाखाल, बुढ़ाकेदार, घनसाली, मयाली, तिलवाड़ा मोटर मार्ग को ऑलवेदर रोड़ (चारधाम प्रोजेक्ट) को जोड़ने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है। बूढाकेदारा-अंयारकाखाल, उत्तरकाशी मोटर मार्ग यातायात के लिए एक दशक पूर्व खोला गया था। यह मार्ग सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुगम बनाने तथा प्राचीन पौराणिक बाबाकाशी विश्वनाथ मंदिर, तथा उत्तरकाशी-बूढाकेदार मंदिर को जोड़ते हुए निर्माणाधीन दो ऑलवेदर रोड़ एन.एच-108 तथा 109 को बीच में सुगमता से जोड़ने तथा दूरी कम करने वाला मार्ग है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सीमांत जनपद उत्तराकाशी के हर्षिल, नेलांग में स्थित आर्मी कैंप से सीमांत चमोली के जोशीमठ, माणा में स्थित आर्मी कैंप जोड़ने वाला मार्ग है।

उपरोक्त वार्णित मार्ग पर पड़ने वाले अविकसित पौराणिक व प्राकृतिक सौदर्य वाले स्थल को मानचित्र पर पहचान मिल सकेगी तथा उत्तरकाशी स्थित बाबा काशीनाथ, बूढाकेदारनाथ के दर्शन व पवित्र नदी मां भागीरथी में, स्नान के लिए सीमांत क्षेत्र की जनता को वर्षभर हर मौसम में सुविधा मिलती रहेगी।

अतः मेरा केन्द्रीय मंत्री से आग्रह है कि जनभावनाओं को मध्य नजर रखते हुए उपरोक्त मार्ग को ऑलवेदर राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु स्वीकृति देने की कृपा करें।

(vii) Need to accord approval to the drinking water and irrigation project for Churu Parliamentary Constituency and Shekhawati Region in Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे लोकसभा क्षेत्र चुरू व शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल व सिंचाई का जल पहुँचाने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पर भारत सरकार द्वारा कार्य किया गया था, जिसके तहत ताजेवाला हेड से पाइपलाइन के माध्यम से यमुना नदी का जल मेरे क्षेत्र में पहुँचाने की योजना बनाई थी। भारत सरकार द्वारा इस हेतु हवाई सर्वे करवाकर कार्य भी पूर्ण कर लिया गया था, व राजस्थान सरकार को निर्देश भी जारी कर दिए गए थे कि इस योजना हेतु डीपीआर बनाये जाने का कार्य शुरू किया जाये। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार द्वारा इस हेतु डीपीआर बना कर भारत सरकार के पास भिजवा दी गई थी, जिसके तहत इस योजना पर कुल 20 हजार करोड़ रूपये की राशि का व्यय होना बताया गया था, जिसमे से 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने का भी प्रावधान था। लेकिन आज तक इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी नहीं की गई हैं। चुरू लोकसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा रेगिस्तानी इलाका हैं और यहाँ जल की भारी कमी हैं। इसके योजना के तहत मेरे गृह तहसील राजगढ़ का जो हिस्सा लाभान्वित होगा वह पहले से ही डार्क जोन घोषित किया हुआ हैं व इस क्षेत्र में कुंओं का जलस्तर भी लगातार घटता जा रहा हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध हैं की चुरू लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ शेखावाटी क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जावे ताकि हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकें।

(viii) Regarding development of Jhansi and Lalitpur districts in Uttar Pradesh

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद झांसी ललितपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं, जनपद झांसी व ललितपुर 1974 के पूर्व एक ही जनपद हुआ करते थे, जिसका कि अब भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी सियासी गलियारों में गिड़गिड़ाता बुंदेलखंड अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी की अनुकंपा से बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलने जा रही है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विगत वर्षों में डिफेंस कॉरिडोर, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हेतु घोषणा की थी, जो अब मूर्त रूप लेने जा रही है ,कोशिशें परवान चढ़ी तो वह दिन दूर नहीं जब बुंदेलखंड में कारखानों की एक लंबी श्रृंखला होगी, इसी क्रम में ललितपुर हवाई पट्टी, झांसी हवाई पट्टी की कार्यवाही चल रही है। वर्तमान में खेती पर निर्भर बुंदेलखंड में सरकार के सहयोग से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एवं फूड प्रोसेसिंग के संबंध में भी कार्यवाही आगे बढ़ रही है। विशेषता दलहन ,तिलहन ,मटर ,अदरक, मूंगफली आदि के उत्पादक क्षेत्र बरुआ सागर, मऊरानीपुर, चिरगांव ,बबीना, तालबेहट ,जाखलौन, महरौनी ,बिरधा आदि क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण की छोटी छोटी इकाइयां विकसित करने हेतु लोग आगे आ रहे हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में ललितपुर में आटा मिल भी स्थापित की गयी है । इन सब कार्यों से बुंदेलखंड वासियों को नियमित रूप से रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका के माध्यम से क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के रूप में प्लेटफार्म उपलब्ध हुआ है, जिससे यहां के दुग्ध उत्पादकों को सही मूल्य एवं एवं नियमित बैंकिंग भुगतान प्राप्त हो रहा है एवं कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी हो रही है।

खनिज संपदा बुंदेलखंड क्षेत्र में विगत शताब्दियों से पन्ना क्षेत्र हीरा उत्पादन के लिए विख्यात है, अब यहां हिनौता, मझगवां तथा छतरपुर जनपद के अंगोर नामक स्थान में भी हीरा प्राप्त होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं , हीरा उत्पादन से करोड़ों रुपए की रॉयल्टी प्रांतीय सरकार को प्राप्त होती है। बुंदेलखंड में वास्तु पत्थर के अच्छे भंडार हैं। ग्रेनाइट पत्थर अपनी गठन, कठोरता तथा सुंदरता के कारण अलंकरण पत्थर के रूप में प्रसिद्ध है। विदेशों में जर्मनी, जापान, इटली में इसकी वृहद मांग है।कांच उद्योग में प्रयोग होने वाली बालू के निक्षेप इतने बड़े हैं कि संपूर्ण भारत की 80% मांग यहीं से पूरी हो सकती है अनेक स्थानों में सिल्का की मात्रा 99.2% है ,गोरा पत्थर भी कई स्थानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बुंदेलखंड में पाए जाने वाले खनिजों में फोस्फेराइट , गैरिक जिप्सम, लौह अयस्क, अन्य अमूल्य रत्न आदि है।

संभावित खनिजों की सूची में तांबा ,सीसा ,निकिल, टंगस्टन ,चांदी, सोना आदि है ललितपुर में अनुमानत: 10 करोड़ टन खनिज का भंडार है इसमें से 35% से 67% लोहा प्राप्य है जो स्पंज आयरन हेतु उपयोगी है। सुनरइ ललितपुर में 400 मीटर से 1000 मीटर लंबे तथा 1 से 3 मीटर मोटे ताम्र अयस्क भंडार हैं। जिनमें 0. 5 प्रतिशत तांबा है यहां पर जो ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती हैं, यह चट्टाने अधिकतम रेडियोधर्मी यूरेनियम युक्त होती हैं, ललितपुर में हुए सर्वेक्षण के द्वारा इस संभावना को बल मिला है। महोदय बुंदेलखंड को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए निम्न बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है। झांसी जनपद मैं यहां के खाद्य उत्पाद मटर, अदरक, दलहन, तिलहन ,मिल्क उत्पाद, रानीपुर टेरीकॉट प्रोसेसिंग की स्थापना हेतु आर्थिक सहयोग व विभिन्न प्रकार की सब्सिडी की आवश्यकता है।

मेरा निवेदन है कि भारत सरकार इस प्रकार की नीति विकसित करें जिससे कि जनपद झांसी,ललितपुर में विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट आसानी से स्थापित की जा सके। बुंदेलखंड के छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बुंदेलखंड में 100 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु भूमि

खरीद के लिए ऋण लेने पर शत प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया जाए। श्रमिकों के लिए हॉस्टल या डॉरमेट्री सरकारी खर्चे पर बनवाए जाएं। औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए भूमि खरीद पर बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु शत प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट प्रदत्त की जाए. फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए इसे मंडी शुल्क से मुक्त किया जाए. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 साल तक छूट का प्रावधान रखा जाए। झांसी स्थित बी एच ई एल को अधिक से अधिक सरकारी वर्क आर्डर दिलाए जाने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाए।

(ix) Regarding running of Vande Bharat Train between Delhi and Gorakhpur and Shatabdi Express on Lucknow-Gorakhpur-Varanasi Railway section

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): दिल्ली से गोरखपुर वन्दे भारत ट्रेन व लखनऊ गोरखपुर वाराणसी रेल खण्ड पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाए।

(x) Regarding Open Shelter Home for Orphan children run by Laveena Vikas Seva Sansthan, Ogana in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मैं माननीय मंत्री जी कि संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में लविना विकास सेवा संस्थान ओगना जो कि ओपन शेल्टर होम 21 सितम्बर 2017 से चला रहे है। इनके द्वारा जनजाति बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र में बीटी कॉटन कपास की मजदूरी करने वाले अनाथ बालकों को निवासरत किया जाता है। बताना चाहूंगा कि जिला के कलेक्टर एवं अन्य जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी द्वारा संतोषप्रद निरीक्षण किया जा चुका है और मैं स्वयं भी इनके संस्थान गया हूँ और इनके काम को जाना और समझा तथा रह रहे बालको से भी मिला हूँ। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज तक दुर्भाग्यपूर्ण इनको पिछले 4 वर्षों से कोई भुगतान नहीं हो पाया है। मुझे इस बात से भी अवगत करवाया गया है कि संरक्षक पिछले साढ़े तीन साल से कर्ज लेकर इन बालकों का भरण पोषण कर रहे है।

अत: मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि तत्संबंधित अधिकारी को इस विषय पर जांच करवाने के आदेश देवे और साथ ही इनका भुगतान जल्द से जल्द करवाने के आदेश जारी करें। इसके लिए मैं तथा संस्थान और वहां रह रहे बालक आपके सदा आभारी रहेंगे और कम से कम उन्हें राइट तो फूड का हक़ मिल सके।

(xi) Regarding railway related issues in Haryana

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): गाडी संख्या 14021/22 सैनिक एक्सप्रैस का ठहराव सतनाली पर पुन: बहाल किया जाए-

ट्रेन संख्या 22471/72 बिकानेर-दिल्ली इंटरसिटी का ठहराव सतनाली स्टेशन पर किया जाए।

दैनिक यात्रियों की मांग पर रोहतक से जयपुर वाया झज्जर - अटेली और नारनौल नई डी.एम.यू. ट्रेन चलाई जाए।

सीकर से रेवाड़ी वाया अटेली और नारनौल नई डी.एम.यू. ट्रेन चलाई जाए।

लोहारु से भिवानी नई रेलवे लाईन को बिछवाया जाए।

भिवानी से रोहतक रेल लाईन का दोहरीकरण किया जाए।

ट्रैन संख्या 54423/24 (हिसार-भिवानी-रोहतक-दिल्ली) सवारी गाडी को एक्सप्रेस किया जाए।

अलवर – महेंद्रगढ – दादरी के लिए नई रेलवे लाईन बिछवाई जाए।

ट्रेन संख्या 09416 का चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव करवाया जाए।

(xii) Regarding early construction of Chiraiya-Diphi-Ghorasahan road in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सरकार का ध्यान अपने शिवहर संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत चिरैया-दिपही-घोड़ासहन रोड की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। ज्ञात हो कि उक्त सड़क चिरैया एवं घोड़ासहन प्रखण्ड को जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है। सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा आवागमन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आये दिन यहाँ छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है।

अतः सरकार से अनुरोध होगा कि जनहित में उपरोक्त चिरैया-दिपही-घोड़ासहन रोड के शीघ्र निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(xiii) Regarding alleged flouting of environmental norms at stone quarrying sites in Aurangabad district, Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार के औरंगाबाद जिले में रफीगंज अंचल के पचार तथा मदनपुर अंचल के सैंडल पत्थर खदानों में खनन मानदंडो का उल्लंघन किया जा रहा है। पत्थर खनन के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत पट्टाधारी को कुछ शर्तें यथा रात्रि में खनन रोकना, कंक्रीट पिलरों का ढाला जाना, पर्यावरण रक्षा हेतु वृक्षा रोपण करना आदि मानने की बाध्यता होती है। किन्तु दोनों ही स्थानों पर खनन में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर न सिर्फ रात में इन खदानों का दोहन जारी है बल्कि नियम विरुद्ध न तो हरित पट्टी विकसित की जा रही है न ही खनन स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु GI शीट का उपयोग किया जा रहा है बल्कि नियम विरुद्ध अधिक गहराई तक ड्रिलिंग कर पत्थर तोड़ने का कार्य जारी है। रफीगंज में खनन स्थल के निकट ही जैन मंदिर, एक मस्जिद तथा हिन्दू धर्मस्थल भी है। बड़े विस्फोटों से निकट बसी आवादी के घरों एवं इन धार्मिक स्थलों के भवनों को भी क्षति पहुँच रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड इन खनन स्थलों कि जांच करें तथा खनन शर्तें न पूरा करने कि स्थिति में तत्काल प्रभाव से खनन प्रतिबंधित किया जाए।

(xiv) Regarding proper resolution to railway related issues of Shirdi Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री सदाशिव किसान लोखंडे (शिर्डी): मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान शिर्डी-अहमदनगर-पुणे इंटरसिटी रेल सेवा प्रारम्भ किए जाने तथा बेलापुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 16229 (मैसूर-सोलापुर-वाराणसी) और 1211 (पुणे-नागपुर गरीब रथ) के ठहराव दिए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा इस संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री जी का भी पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया है कि बेलापुर रेलवे स्टेशन पर उक्त दोनों रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने की सिफारिश मंडल रेलवे द्वारा बोर्ड को की गयी है, जो अभी तक लंबित है।

मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि शिर्डी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान रेलगाड़ी नं. 51033/51034 सांई नगर-दौंड-पुणे-मुंबई शिर्डी फास्ट पैसेंजर शुरू किए जाने की भी मांग की गई है। इस संदर्भ में भी मेरे द्वारा माननीय रेल मंत्री जी को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की रेल समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

12.09 hrs

VALEDICTORY REFERENCE

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, we must appreciate that the hon. Speaker made elaborate arrangements for the convenience of Members and for smooth conduct of the Session. We express our sincere gratitude to him. A number of Members have also expressed the sentiments regarding well-being of hon. Speaker. His condition is stable now. I, on behalf of the House, wish him speedy recovery.

Hon. Members, we have now come to the close of the 5th Session of the 17th Lok Sabha which commenced on the 29th January, 2021. We had 24 Sittings spread over 131 hours and 56 minutes.

Hon. President addressed the Members of both the Houses, assembled together on 29th January, 2021. The discussion on Motion of Thanks on the President's Address lasted for 16 hours and 58 minutes and as many as 149 Members took part in the discussion.

Hon. Prime Minister replied to the Debate. The House adopted the Motion unanimously. The Union Budget was presented by the Minister of Finance on 1st February, 2021. The General Discussion on Union Budget lasted for 14 hours and 42 minutes. As many as 146 Members took part in the Debate and Minister of Finance replied to the discussion.

The Demands for Grants 2021-22 under the control of the Ministries of Railways, Education, Health and Family Welfare were discussed. A total time of 21

hours and 43 minutes was spent on debates. The discussions were concluded with the replies of Ministers concerned. All the remaining outstanding Demands for Grants in respect of Union Budget for 2021-22 of the remaining Ministries were submitted to the vote of the House and voted in full on 17th March, 2021 and the related Appropriation Bill was passed.

During this Session, 17 Government Bills were introduced. In all, 18 Bills were passed. Some of the important Bills which were passed are the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021; the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021; the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021; the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021; the Insurance (Amendment) Bill, 2021; the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021; the Marine Aids to Navigation Bill, 2021; the Finance Bill, 2021, the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021 and the Juvenile Justice (Care and Protection) of Children (Amendment) Bill, 2021.

Eighty-four Starred Questions were orally answered. A total of 583 Matters of Urgent Public Importance were raised by the Members after Question Hour and by sitting late in the evening. A total of 406 matters under Rule 377 were taken up.

The House also held a discussion on one Calling Attention regarding Women Empowerment which was later converted into a Short Duration Discussion under Rule 193. The Standing Committees presented 163 Reports to the House.

As many as 48 Statements under Direction 73A and 5 *suo motu* Statements were made by the Ministers. Three Statements by Minister of Parliamentary Affairs regarding Government Business were also made. During the Session, as many as 3591 papers were laid on the Table.

Hon. Members, I am pleased to inform that under the able guidance of the hon. Speaker and with cooperation from hon. Members, the productivity of this Session of Lok Sabha stood at 114 per cent. Coming to the Private Members' Business, a Resolution regarding welfare measures for Anganwadi workers and Anganwadi helpers was moved by Shri Ritesh Pandey on 20 March, 2020 during the Third Session and was further discussed on 12 February and 19 March, 2021 during the current session and discussion thereon did not conclude.

I would like to thank my hon. colleagues in the Panel of Chairpersons for their co-operation in the completion of Business of the House. I am extremely grateful to the Hon'ble Prime Minister, Ministers of Parliamentary Affairs, Leaders of various parties as well as the Hon'ble Members for their cooperation.

I would also like to thank, on behalf of all of you, our friends in the Press and the Media. I take this opportunity to compliment the Secretary-General and the officers and staff of the Lok Sabha Secretariat for their dedicated and prompt service to the House. I also thank the allied agencies for their able assistance in the conduct of the proceedings of the House.

HON. CHAIRPERSON: Hon'ble members may now stand up as '*Vande Matram'* would be played.

12.13 hrs

NATIONAL SONG

The National Song was played.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned *sine die*.

12.15 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.